



04 - मागवत के शतावी
संगत से निकले सदेश



05 - दूसरी सा जीवन घले
घले घमक उठा है

A Daily News Magazine

मोपाल

जैगलगाव, 09 सितंबर, 2025



वर्ष 23, अंक 12, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - शिक्षक ही भारत भगवत
विधान और शहर निर्माता
है : श्रीधर बर्मे



07 - राजस्व मामले
तहसील में ही नियकृत
करें ताकि नागरिकों...

मोपाल

मोपाल

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsaverenews
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मोहब्बतों में दिखावे की
झड़ोस्ती न मिला
अगर गले नहीं मिलता
तो हाथ भी न मिला
घरों पे नाम थे नामों के
साथ ओहदे थे
बहुत तलाश किया
कोई आदमी न मिला
तमाम इश्तों को मैं
घर पे छोड़ आया था
फिर उस के बाद मुझे
कोई अजनबी न मिला
खुदा की झटनी बड़ी
काएन तम मैं मैं ने
बस एक शख्स को माँगा
मुझे वही न मिला
बहुत अजीब है ये
कुर्बानों की दूरी भी
वो मेरे साथ रहा और
मुझे कभी न मिला

- बशीर बद्र

प्रसंगवद्धि

पंजाब-बाढ़ ने आप की अंदरूनी कलह को सामने ला दिया?

पं

जाब में आई बाढ़ आपदा ने आम आदमी पार्टी की अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक मतभेदों को उजागर कर दिया है। जानें कैसे राहत कार्य और प्रबंधन की कामियों से पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए।

बाढ़ ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह को भी उजागर कर दिया है। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अपने संकट को निपटना में लगी है। एक नई प्रवेशासाला आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब बन गया है। पार्टी के अपने एक अंदरूनी सर्वेक्षण में सामने आया है कि भगवत मान का ग्राफ भी पंजाब में गिर रहा है और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। चर्चाएँ हैं कि लोगों में मुख्यमंत्री भगवत मान को से उमीदें टूट चुकी हैं कि वो मजबूती से कुछ निर्णय कर पाएंगे।

%दिल्ली लंबी% कथित तौर पर प्रशासन में हस्तांतरण कर रही है और अपना नियंत्रण बनाये हुए है। उसकी चर्चाएँ पूरे पंजाब में आम तौर पर लोगों में होने लगी हैं। मुख्यमंत्री भगवत मान का अरविन्द केजीरावल के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के द्वारे पर न जाने और अचानक उनकी तबियत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती होने से अलग-अलग कायास लगाए जा रहे हैं। सियासी हल्कों में कुछ घटनाओं को संकेत के तौर पर भी परवाह जाता है। निरंतर पंजाब में सक्रिय रूप से वाले अरविन्द केजीरावल ने बाढ़ के हालात में कई दिनों बाद पंजाब की सुध ली

है। सबसे पहले बाढ़ की चेपेट में आये जिला गुरदासपुर अमृतसर की बजाये के जीरीवाल और मनीरी सिसोदिया ने पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा उस दिन किया जब उनकी दिल्ली की अदलत में शराब घोटाले के ममले में पेशी थी। मुख्यमंत्री भगवत मान चाहते थे कि पहले अमृतसर, गुरदासपुर, अजनाला, बटाला का दौरा किया जाये क्योंकि यात्रा लगाया जाने लगा है कि अरविन्द केजीरावल के पंजाब पर नियंत्रण की कोशिश में भगवत मान को राजस्वसभा जाने को कहा गया है।

2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की फिर से जीत की संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए केजीरावल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करने के तौर पर अमृतसर सांख्य से विधायक और कैविटेंट मंत्री नए सिख चेहरे इंद्रलीला सिंह निजात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किन्तु ग्रोम स्पीकर भी नियुक्त किया गया था। साथ में उप-मुख्यमंत्री के तौर पर हिन्दू चेहरा अमन अरोड़ा और पंजाब में एक बड़े वर्ग अनुशूलित जाति को साधनों के लिए वर्तमान वित्त मंत्री हुपाल सिंह चीमा को लाना चाहते हैं। भगवत मान इस पर आपत्ति को अपनी सियासी मजबूती की वजह से व्यक्त करने में असमर्थ है। पिछले साल 2024 में भगवत मान को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा कर हिन्दू चेहरा अमन अरोड़ा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। केजीरावल के प्रदेश में मतदाताओं के नए राजनीतिक समीकरण गढ़ने की रणनीति पर चलते हुए हासिल हो रही है।

पटियाला जिले के सनारे विधानसभा के विधायक हरमीत सिंह पठनमाजरा ने जिस तरह बाढ़

के लिए प्रदेश सरकार पर सवाल उठाये और कथित %दिल्ली% की लूट को अब्दली की लूट से बड़ा बताया उससे भी पंजाब की स्थिति अब भी बद्दी हल्की हो गयी है। इस घटना ने भगवत मान और अरविन्द केजीरावल के बीच की खाई को और बढ़ा दिया है। हमीर सिंह पठनमाजरा ने मुख्यमंत्री भगवत मान को दिल्ली के बजाय पंजाब के हिंतों के लिए खड़ा होने और अन्य विधायकों को भी साथ लेने की बात की।

पंजाब में जिस तरह %दिल्ली% के नियंत्रण का ढांचा बनाया गया है उससे पंजाब के बहुत से विधायक असंतुष्ट हैं। कई विधायकों के आगमी चुनावों में टिकट कटने का आकाशकांओं के चलते भी एक चर्चा बढ़ रही है।

1988 में पंजाब में अभूतपूर्व बाढ़ की स्थितियाँ बड़ी थीं जिसके बाद प्रदेश में सरकार के प्रति एक बड़ा आकोश प्रदेश में उभरा था। वर्तमान में पंजाब की सीमा से लगते हुए 8 जिलों को बाढ़ ने अपनी चपर में लिया है। पठनमाकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, तरनतारण, फिरोजपुर, पाली और चंडीगढ़ के खेतों में खड़ी धान की फसल लगभग डूब गई है। सबसे बड़ी मौसमी विधायिकों पर बन आई है। पंजाब के किसानों की रीढ़ बेजुबान जानवरों के बचाव के लिए और उनके चारे और बीमारियों से बचाव की व्यवस्था के कितने पुख्ता प्रबंध किये गए हैं, ये साफ नहीं। बाढ़ के बाद पुनर्वास और जनजीवन में होनेवाली कटनाइयों की चुनौती पंजाब सरकार के लिए बड़ी हो गई है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा है कि

स्थितियाँ काफी बिकट हैं और सरकार की ओर से दूर संभव प्रयास लोगों और मवेशियों की रसा के लिए किये जा रहे हैं। अब सवाल यह भी उन्हें लगता है कि प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र ने मानसून में बाली परिस्थितियों का आकलन समय रहते क्यों नहीं किया? पंजाब की भीमालिक विधियाँ और उसमें से जुटाने वाली नियमों की क्षमता तथा अलग-अलग बांधों का प्रबंधन और आपदा में संचालन पहले से ही तय मानकों के अनुसार किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री भगवत मान और पंजाब सरकार का पूरा तरफ किस लागतों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने में विकल रहा, यह भी होरान करने वाला है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि राज्य की विशेष सहायता दी जानी चाहिए ताकि लोगों को हुँ-नुकसान का उचित मुआवजा समय पर दिया जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव की स्थितियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

अब सवाल पंजाब में सियासी संघर्ष के परिणामों पर टिक गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार और नेतृत्व पंजाब में नयी संभावनाओं पर नज़र बनाये हुए हैं। राजनीति में समझौते और उसकी समय अनुसार आकाश भी लेते हैं। केजीरावल परिवर्तन को प्रेरणा मानते रहे हैं। पिछले वर्ष पंजाब के होशियारपुर में अपनी विश्वयना करने के बाद अरविन्द केजीरावल सीधे अमृतसर पहुँचे थे और उपने ठहरने के लिए इंद्रलीला सिंह के घर की सकत है।

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं

• एससी ने चुनाव आयोग से कहा-इसे 12वां दस्तावेज माना जाए



पटना (एजेंसी)। सुरीम कोर्ट में सेमोवार को बिहार में एसआईआर (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दावर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग की अदेश वाले दस्तावेज के लिए आधार को 12वां दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार एसआईआर के लिए फिलहाल 11 नियरित दस्तावेज हैं जिन्हें मतदाताओं को अपने पार्टी के साथ जमाना होता है। इन्हीं दस्तावेज के तौर पर आधार नामिकता का प्रमाण नहीं होता है। जिसके बाद आधार नामिकता का प्रमाण नहीं होता है। आधार कोर्ट ने यह आधार नामिकता का प्रमाण नहीं होता है। आधार कोर्ट ने यह आधार नामिकता का प्रमाण नहीं होता है। आधार कोर्ट ने यह आधार नामिकता का प्रमाण नहीं होता है।

आधार कार्ड को लेकर अग्र किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध व्यक्ति के बाहर रहे हैं, उन्हें मतदाता सुन्दरी से बाहर रखा जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से शामिल करे। केवल

यूपी के हर विवि कॉलेज की होगी जांच

लखनऊ (एजेंसी)।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदियन्ध की ओर से सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की जांच को लेकर आदेश दिया गया है। एजेंसी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस, प्रशासनिक और शिक्षा अधिकारियों की खास टीम बनाने के लिए दिशा दिया गया है। यह टीम कॉलेजों की मायदान और एडमिशन को लेकर जांच करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वीकृत पाठ्यक्रम ही यूनिवर्सिटी-क

सीएम से गायक मीका सिंह ने समत्व भवन में सौजन्य भेंट की

भोपाल (नप्र)। सिंगर मीका सिंह रविवार रात भोपाल पहुंचे और डीबी स्टारी मॉल के चौथे फ्लोर पर बने स्टूडिओ X O के स्टेज पर पफोर्मेंस दी। सोमवार को उहाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गायक मीका सिंह ने समत्व भवन में भेंट की।

मीका ने गाया- भोपाल न सोया सारी रात - रविवार को शो के द्वारान मीका दर्शकों को पंजाबी अंदाज में सत्त्री काल भोपाल ! कहकर रूबरु हुए और धमाकेदार अंदाज में दमा दम मस्त कलंदर गाने से शुरूआत की। पहले ही गाने पर डांस फ्लोर



थिरक उठा और जब मीका ने साबन में लगा गई आग डैल, तो पूरा करवाए थम उठा। भोपाल न सोया सारी रात गाकर माहोल

को और गरमा दिया। पार्टी का जोश तब और बढ़ा जब मीका ने भोपाल का मौसम बदलनी और लैला तेरी ले लेगी सुनाया। भीड़ हूटिंग और तालियों से गंज उठी। फैशन-लवर्स और युवाओं ने देर रात तक डांस फ्लोर पर थिकते हुए इस म्यूजिक नाइट को मिनी फेस्टिवल में बदल दिया।

मीका ने ऑडियंस से कनेक्ट होते हुए कहा आप सब सूमा भोपाली हो और आज की ये रात आप सबके नामज लव यू भोपाल ! लेट नाइट तक चली इस पार्टी में मीका ने अपना लेटेस्ट ट्रैक लवर बोय भी सुनाया। लवर की गिलटरिंग लाइट्स, डीजे एनकेडी का हाई-वोल्टेज म्यूजिक और मीका का चार्म मिलकर इस शो को यादगार बना गया।

प्रदेश में पति-पत्नी एक साथ बने आईएएस राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 अफसर पदोन्नत



राजेश कुपरारे

नंदा भलाचे कुशरे

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश कैडर के 16 राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएस) अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत किया गया है। इनमें से अधिकारी भी शामिल हैं जो विभागीय जांच के चलते पिछले सालों में प्रोशोन से वर्चित रह गए थे। राजेश कुशरे और नंदा भलाचे कुशरे को एक साथ पदोन्नति मिली है, वे पति-पत्नी हैं।

जांच में कठिनाई चिन्हिणे के बाद नायराण प्रसाद नामदेव और कैलेश कुशरे भी आईएएस बन गए हैं। उज्जैन नार नियम के पूर्व कमिशनर आशीष पाठक को भी आईएएस में पदोन्नति दी गई है। मिसिनग एक पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ड्रिनिंग-डीओपीडी) की ओर से सम्बन्धित को 2023 और 2024 बैच के लिए आईएएस अवॉर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया गया।

इन दोनों ही सालों के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पिछले महीने हुई थी। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन दोनों सालों में 8-8, यानी कुल 16 अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत किया गया है।

2023 बैच में इन्हें सिला-आईएएस बनने का मौका जिन आईएएस अफसरों को 2023 बैच के लिए आईएएस अवॉर्ड का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन दोनों सालों में 8-8, यानी कुल 16 अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत किया गया है।

नायराण प्रसाद नामदेव और डॉ कलाश कुशरा

नंदा भलाचे कुशरे

अनिल कुमार डामोर

सविता ज्ञानिया

सारिका भूमिया

कमल सोलंकी

जितेंद्र खौलान

2024 के लिए इनका हुआ

आईएएस में स्लिक्षण-2024 की डीपीसी के लिए जिन राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का नाम चुना गया है, उनमें ये उज्जैन में पदस्थ टैगर और पूर्व नियमायुक्त उज्जैन आशीष पाठक का नाम शामिल है। जो अधिकारी आईएएस बने उनके नाम हैं।

संतोष कुमार टैगर
निशा डामोर
राकेश कुशरे
शैली कनास
रोहन सक्सेना
कविता बाटला
सपना अनुग जैन
आशीष कुमार पाठक

विभागीय जांच और आयु अधिक होने के कारण नहीं बन पाए आईएएस आईएएस बन गए हैं। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन दोनों सालों में 8-8, यानी कुल 16 अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत किया गया है।

नायराण प्रसाद नामदेव

डॉ कलाश कुशरा

नंदा भलाचे कुशरे

अनिल कुमार डामोर

सविता ज्ञानिया

सारिका भूमिया

कमल सोलंकी

जितेंद्र खौलान

एमपी सरकार को रेपिस्ट को 25 लाख मुआवजा देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट बोला- 7 साल सजा, 11 साल जेल में रखा, रिहा क्यों नहीं किया



भोपाल (नप्र)। सुप्रीम कोर्ट ने ऐप के मामले में दोषी को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सामग्र जिले के इस मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे रिहा किया गया। जिससे जेरी पार्टीवाल और जस्टिस जेरी पार्टीवाल की गिलटरिंग लाइट्स, डीजे एनकेडी का फॉटोटेक्स फॉटकर लगाई। अदालत ने इसे 'गंभीर चक्र' बताते हुए कहा कि इस तरह की अवैध हितास कियी भी हो जाए में स्वीकार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना प्रशासनिक विफलता-सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट/सेटेंस कैलकुलेशन शीट, पैरोल-रिमिशन और अदालत के आदेशों के पालन की पूरी फाइल आज पेश करने को कहा गया था। कोर्ट ने

भोपाल गैस त्रासदी पर सुनवाई

यूनियन कार्बाइड के दोषियों की अपील पर सीबीआई ने रिहा तर्क

भोपाल (नप्र)। भोपाल यूनियन कार्बाइड के भारतीय दोषी अधिकारियों की अपील पर सोबाहर को भोपाल के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन (डीजे) कोर्ट में सुनाई हुई। इस दौरान केंद्रीय अवैधण व्यापर (सीबीआई) ने अपने लियात और मौखिक तर्क कोर्ट के समझ रखा।

संतोष कुमार टैगर
निशा डामोर
राकेश कुशरे
शैली कनास
रोहन सक्सेना
कविता बाटला
सपना अनुग जैन
आशीष कुमार पाठक

विभागीय जांच और आयु अधिक होने के कारण नहीं बन पाए आईएएस-राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों में अब विवेक सिंह, पक्कज शर्मा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा जांचेंद्र कुमार विवाहत, मोज मालवीय, कमल चंद्र नागर, द्वारका प्रसाद बर्मन, कमलता पुरी, सरोधन सिंह का भी विभागीय जांच और आयु सीमा अधिक होने के चलते अपेक्षित अवैध हितास किया गया है। इसी आधार पर भोपाल ट्रायल कोर्ट ने उनके नाम शामिल किया है।

सीबीआई ने रिहा तर्क दिया कि दोषियों द्वारा दायर योग्य नहीं है। एजेंसी ने बताया कि जिन धाराओं को चुनावी दी जा रही है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 1996 के आदेश में बरकरार रखा था। इसी आधार पर भोपाल ट्रायल कोर्ट ने 29 अगस्त 1997 से इन धाराओं पर सुनवाई शुरू की थी।

2011 से लंबित इस आपराधिक अपील जे. मुक्कं, एस.पी. चौधरी और किंवदंत कामरार ने दायर की है। तोन्हे दोषियों का कहना है कि 7 जून 2010 को भोपाल ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला गलत था। इसलिए दंड प्रियंका सहित की धारा 464 के तहत पूरे मामले को पुनः सुनवाई कर नए आपेक्ष तर्क दिया जाए।

सीबीआई ने रिहा तर्क दिया कि दोषियों द्वारा दायर योग्य नहीं है। एजेंसी ने बताया कि जिन धाराओं को चुनावी दी जा रही है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 1996 के आदेश में बरकरार रखा था। इसी आधार पर सुनवाई शुरू की थी।

जांच और आयु अधिक होने के कारण नहीं बन पाए आईएएस-राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों में अब विवेक सिंह, पक्कज शर्मा को फैसला दिया गया था। यह विवेक के नाम शामिल होने के बाद भी उसके लिए अवैध हितास किया गया है। इसके बाद भी उसके लिए अवैध हितास किया गया है।

जांच और आयु अधिक होने के कारण नहीं बन पाए आईएएस-राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों में अब विवेक सिंह, पक्कज शर्मा को फैसला दिया गया था। यह विवेक के नाम शामिल होने के बाद भी उसके लिए अवैध हितास किया गया है।

दोषियों को चुनावी दी जा रही है। एजेंसी ने बताया कि जिन धाराओं को चुनावी दी जा रही है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 1996 के आदेश में बरकरार रखा था। इसी आधार पर सुनवाई शुरू की थी।

सीबीआई ने रिहा तर्क दिया कि दोषियों द्वारा दायर योग्य नहीं है। एजेंसी ने बताया कि जिन धाराओं को चुनावी दी जा रही है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 1996 के आदेश में बरकरार रखा था। इ

